भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1396
मंगलवार, 12 दिसंबर, 2023/21 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (पीएसीएस) को राष्ट्रीय एकीकृत सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाना

1396. श्री राजू बिस्ता

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों (पीएसीएस) को राष्ट्रीय एकीकृत सॉफ्टवेयर से जोड़ा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त लिंकिंग से पैक्स की दक्षता में किस प्रकार वृद्धि होगी?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): जी हां, मान्यवर। भारत सरकार द्वारा प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (PACS) को सशक्त करने के लिए 2,516 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से 63,000 कार्यशील पैक्स के कंप्यूटरीकरण की परियोजना अनुमोदित की गई है जिसमें सभी कार्यशील पैक्स को ईआरपी (एंटरप्राइज़ रीसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर साथ लाकर उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक करना शामिल है । 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 62,318 पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी हैं। नाबार्ड द्वारा सॉफ्टवेयर का विकास किया जा चुका है और अब तक 26 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 5,673 पैक्स में ईआरपी परीक्षण आरंभ हो चुका है । राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा हार्डवेयर की खरीद और लीगेसी डाटा के डिजिटलीकरण के कार्य प्रक्रियाधीन हैं ।

यह परियोजना त्वरित ऋण संवितरण, लेनदेन लागत में कमी, भुगतानों के असंतुलनों में कमी, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के साथ निर्बाध लेखांकन सुनिश्चित कर पैक्स की कार्यकुशलता में सुधार और पारदर्शिता में वृद्धि लाएगी । यह किसानों के बीच पैक्स के कार्यान्वयन के प्रति विश्वसनीयता बढ़ाएगी ।

*****